भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3937

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क योजना

3937. श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ईएचटीपी योजना के अंतर्गत स्थापित/अनुमोदित इकाइयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ईएचटीपी समर्थित इकाइयों द्वारा विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मात्रा और मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

है; (घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ईएचटीपी इकाइयों द्वारा सृजित निर्यात मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) शुल्क में छूट, कर लाभ और अन्य सहायता उपायों सहित ईएचटीपी इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और वित्तीय लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ईएचटीपी योजना के अंतर्गत निवेश को बढ़ावा देने और भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): ईएचटीपी योजना भारत से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 100% निर्यात-उन्मुख योजना है और एसटीपीआई ईएचटीपी योजना के तहत सिंगल-विंडो मंजूरी प्रणाली पर सांविधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। ईएचटीपी योजना के तहत कोई निधि आवंटन नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के लिए ईएचटीपी इकाइयों के बारे में विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
ईएचटीपी इकाइयों की कुल संख्या	70	73	79
ईएचटीपी इकाइयों द्वारा कुल निर्यात (करोड़ रुपये में)	9,678	11,443	11,102*

*अनुमानित

पिछले तीन वर्षों में ईएचटीपी योजना के तहत स्थापित/अनुमोदित ईएचटीपी इकाइयों और उनके निर्यातों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है -

ईएचटीपी योजना के तहत स्थापित/अनुमोदित इकाइयों की संख्या और पिछले तीन वर्षों में निर्यात का ब्यौरा (राज्य-वार)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26	
		ईएचटीपी इकाइयों की संख्या	निर्यात (करोड़ रुपये में)	ईएचटीपी इकाइयों की संख्या	निर्यात (करोड़ रुपये में)	ईएचटीपी इकाइयों की संख्या	निर्यात* (करोड़ रुपये में)
1	गोवा	1	78.41	1	47.3	1	37.19
2	गुजरात	1	5.11	1	6.95	1	6.38
3	हरियाणा	4	305.91	4	243.57	4	270.88
4	कर्नाटक	29	6,835.26	32	9,338.93	34	8,328.98
5	केरल	1	15.92	1	17.47	2	15.75
6	महाराष्ट्र	7	830.24	6	836.30	6	1,165.54
7	ओडिशा	1	-	1	-	2	-
8	पंजाब	2	3.6	2	9.08	2	0.2
9	राजस्थान	1	110.17	1	38.46	1	46.73
10	तमिलनाडु	12	313.96	12	195.10	14	314.62
11	तेलंगाना	2	1.87	2	1.48	2	2.58
12	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2	11.30	2	10.59	2	12.55
13	उत्तर प्रदेश	6	1,166.23	7	697.43	7	900.41
14	पश्चिम बंगाल	1	-	1	-	1	-
		70	9,677.98	73	11,442.66	79	11,101.81

*अनुमानित

पात्र ईएचटीपी इकाइयों को उपलब्ध प्रोत्साहन और वित्तीय लाभ विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसमें शामिल हैं:

- विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अध्यधीन, निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों, कलपुर्जों और अन्य अनुमत वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/खरीद
- विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) की बिक्री की अनुमति
- सरलीकृत सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और सिंगल-विंडो वैधानिक मंजूरी सहित अन्य परिचालन और प्रक्रियात्मक लाभ

ईएचटीपी योजना के तहत निवेश को बढ़ावा देने और भागीदारी का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- वैधानिक सेवाओं का स्वचालन: ईएचटीपी इकाइयों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए, एसटीपीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैधानिक सेवाओं, उनकी स्वीकृति और अंतिम सूचना को स्वचालित कर दिया है। इससे उद्योग की संतुष्टि के अनुरूप सेवाओं की त्वरित प्रदायगी सुनिश्चित हुई है।
- आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण: हर मामले के आधार पर आयात की अनुमति देने की पुरानी व्यवस्था की जगह, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए एकमुश्त आयात अनुमति की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
- संवर्धन और उद्योग आउटरीच: ईएचटीपी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित हितधारक परामर्श, जागरूकता कार्यक्रम, उद्योग बातचीत और व्यापार कार्यक्रमों में भागीदारी का आयोजन किया जाता है।

*****